किसान आन्दोलन: खट्टर झुके तो ऐसे कि लम्बे ही लेट गये

करनाल (म.मो.) सुधी पाठकों ने गतांक में पढ़ा था कि किस तरह किसानों व खट्टर सरकार के बीच खींचतान चल रही है। बसतारा टोल नाके पर पुलिस द्वारा किसानों के सिर फ़ोड़े जाने को लेकर उनकी ओर से सरकार के सामने कुछ बड़ी साधारण सी एवं न्यायपूर्ण मांगे रखी गई थी। खट्टर द्वारा उन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय उन्हें ललकारते हुए धमकाया। अपनी अपार शक्ति की धमकी देते हुए किसानों को किसी प्रकार का आन्दोलन न करने को कहा।

लेकिन किसान खट्टर की औकात से भली-भांति परिचित थे। उन्होंने खट्टर की 'अपार शक्ति' का नमूना कुछ माह पूर्व घरोंडा में व कुछ समय बाद हिसार में देख लिया था। किसानों ने तो खट्टर की इस 'अपार शक्ति' का आंकलन सही से कर लिया था, परन्तु अपनी अल्पज्ञता के चलते खट्टर किसानों की शक्ति का सही आंकलन न कर सके, लिहाजा दोनों ओर से शक्तियों का प्रदर्शन होते जनता ने चौड़े में देखा और पाया कि खट्टर जी थोड़ा झुकने के बजाय पूरी तरह से किसानों के सामने लमलेट हो गये।

किसानों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने के लिये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देवेन्द्र सिंह को भेजा गया। उन्होंने किसानों की बात मानते हुए, सिर फ़ोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम को लम्बी छुट्टी पर भेजने के साथ-साथ, पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश से कराने का आश्वासन दिया। मृतक किसान के घर से किसी एक को नौकरी देने की जगह दो को नौकरी देने की बात मानी।

रही बात मृतक व घायलों को नकद मुआवजा देने की तो इस पर स्थिति अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है। अनेकों स्थानीय चैनल लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों को कैश मुआवजा दे दिया गया है। जबकि दूसरी ओर प्रशासन अभी इस पर विचार करने की बात कह रहा है। यह एक बड़ा विरोधाभास है। जानकार यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि कई बार सरकार इस तरह के मुआवजे अपने सरकारी खजाने से न देकर 'दायें-बायें' से दो नम्बर में भी अदायगी करा देती है। इस तरह के कुछ मामले पहले से ही मज़दूर मोर्चा के संज्ञान में हैं।

कुल मिलाकर खट्टर ने यह जो काम आठ-दस दिन तनाव में रहकर, पूरे प्रशासन को तनाव में रख कर व भारी-भरकम पुलिस जमावड़ा लगा कर सरकारी धन बर्बाद करके किया है, बिना यह सब किये भी हो सकता था। लेकिन इस के लिये राजनीतिक सूझ-बूझ की जरूरत होती है जो खट्टर के आस-परोस तक में भी नहीं है।

क्या अगला नम्बर खट्टर का लगने वाला है ?

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

दो बार उत्तराखंड, एक बार कर्नाटक और एक बार गुजरात का मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब अगला नम्बर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का लगने वाला है। राजनीतिक हल्कों में यह चर्चा आजकल काफ़ी गर्म है। इसी सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खट्टर की पेशी मांगे जाने से यह चर्चा अब कुछ ज्यादा ही गर्म हो गयी है।

बेशक पेशी भुगतने के बाद नकली मुस्कान के साथ खट्टर ने बाहर आकर बताया कि वे तो मोदी को राज्य की स्थिति विशेष कर करनाल में चल रहे किसान धरने आदि के बारे में बताने आये थे। अजी खट्टर साहब किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या मोदी जी आपके बताने के भरोसे बैठे हैं? उनके पास पल-पल की लाइव रिपोर्टिंग पहुंचती रहती है और फिर यह मामला तो वैसे भी निपट चुका है, बेशक सरकार की पूरी फजीहत कराने के बाद राजनीतिक विशलेषक मानकर चल रहे हैं कि खट्टर ने अपने पूरे सात साल के कार्यकाल में कभी भी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय नहीं दिया, परिचय तो वे तब देते न जब वह उनके पास होती। रही सही कसर उन्होंने इस किसान आंदोलन के दौरान निकाल दी। बीते करीब 10-11 महीनों में उनकी व्यक्तिगत फजीहत के साथ-साथ जो फजीहत पूरी सरकार एवं भाजपा की हुई है, उससे केन्द्रीय नेतृत्व का परेशान होना स्वाभाविक है। इसके अलावा प्रदेश भर में जिस तरह भ्रष्टाचार व लूट का कारोबार चल रहा है, उससे भी भाजपा की छवि रसातल में पहुंच चुकी है। जानकार तो यहां तक भी बताते हैं कि बीते दिनों खट्टर द्वारा फरीदाबाद के सीपी ओमप्रकाश सिंह के घर लंच करने व उन्हें खुली लूट का परमिट देने को लेकर भी मोदी ने इन्हें हड़काया था।

दरअसल मोदी की नीति यही है कि जनता को बहकाने के लिए वे सीएम बदलकर यह संदेश देना चाहते हैं कि सारी बदइन्तजामी भ्रष्टचार आदि के लिए जो सीएम जिम्मेवार था, उसे बदल दिया गया है और अब सब ठीक हो जायेगा। वास्तव में ठीक कुछ नहीं होना होता। भाजपा द्वारा मनोनीत तमाम सीएम मोदी द्वारा तय नीतियों का ही पालन करते हैं और लूट का माल ऊपर तक पहुंचाते हैं। इसलिये बड़ी दुविधा यह भी है कि नया वफादायर प्यादा किसे बनायें?

अदालतें अपने ऊपर मुकदमों का बोझ स्वयं लादती हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) देश भर की अदालतों में मुकदमों का इतना भारी भरकम बोझ लदा है कि पीढियां गुज़र जाती हैं फैसले के इन्तज़ार में। मज़े की बात तो यह है कि ज्यों-ज्यों अदालतों की संख्या बढती जा रही है त्यों-त्यों मुकदमों का भार भी बढ़ता जा रहा है। यह भार कैसे बढ़ता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत है।

जुलाई 2017 में एक दोपहर जब यह संवाददाता अपने घर पहुंचा तो पाया कि थाना कोतवाली का एक सिपाही सिविल में घात लगाये बैठा था, जो देखते ही सामने आ खड़ा हुआ। एक काग़ज दिखाते हुए बोला कि या तो 27000 रुपये तुरन्त भर दो वरना गिरफ़्तार करेगा। काग़ज को पढ़ने से पता चला कि वह स्थानीय कोर्ट द्वारा किये गये एक फ़ैसले के क्रियान्व्यन (इजरा) का आदेश था जो कोर्ट ने टेलिफ़ोन विभाग के हक में एकतरफ़ा सुनवाई करके वसूली का आदेश जारी कर दिया था। सिपाही को जैसे-तैसे टरकाया और तुरन्त मिसल मुआयना कराने पर पता चला कि टेलिफ़ोन विभाग ने दो-तीन साल पूर्व अदालत में अपना बकाया बिल वसूली का केस दायर करके अपने हक में फैसला करा लिया था। एकतरफ़ा इसलिये कि न्यायिक प्रक्रिया में छोड़ी गयी खामियों का फ़ायदा उठाते हुए इस संवाददाता तक केस की भनक तक नहीं पहुचने दी।

वकील द्वारा फाइल निरीक्षण के बाद अदालत में दरखास्त लगा कर बताया गया कि टेलिफ़ोन विभाग का दावा एकदम झूठा व बेबुनियाद है तथा हेराफ़ेरी करके एक तरफा फ़ैसला अदालत से प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए दरखास्त रद्द कर दी। तत्कालीन सैशन जज दीपक गुप्ता की कोर्ट में अपील डाली गयी; उन्होंने पूरे मामले को समझा अपील स्वीकार करते हुए सम्बन्धित कोर्ट को पुन: सुनवाई करने का आदेश दिया। इस पुनसुनवाई में कोर्ट को दस्तावेज़ों सहित बताया गया कि कैसे विभाग ने 500 रुपये मासिक का प्लान देकर 4500 रुपये का बिल भेजना शुरू कर दिया। इस तरह का पहला बिल आते ही इस संवाददाता ने विभाग के अफ़सरों से मिल कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें तो बात करने तक की फुर्सत नहीं थी। लिहाजा वहीं के वहीं दरखास्त लिख कर विभाग से रसीद करा ली। इसमें लिखा गया था कि गलत बिल को ठीक कर दें वरना इसे तुरंत काट दें।

इस दरखास्त का जवाब देने की बजाय बढे हुए बिलों के आने का सिलसिला करीब चार-पांच माह तक चलता रहा। संवाददाता भी हर माह उसी तरह का पत्र लिख कर विभाग से रसीद लेता रहा। जब बिल 27000 के करीब हो गया तो कनेक्शन काटा गया। इसके कुछ वर्ष बाद विभाग ने समझौता वार्ता शुरू तो की लेकिन ग़लत बिल पर अड़े रहे। ऐसे समझौता क्या खाक होना था।

इसके बाद विभाग ने षडयंत्र करके बिल वसूलने की योजना बनाई। पहली सीढी पार करके कोर्ट से अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर ली। लेकिन जब दोबारा सुनवाई हुई और संवाददाता द्वारा विभाग को लिखे पत्र पेश किये गये तो उनकी, एक बार तो, सिट्टी-पिट्टी गुम हो गयी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने इस संवाददाता के फ़र्जी हस्ताक्षर करके, एक फ़र्जी दस्तावेज तैयार कर लिया जिसके अनुसार कोर्ट में पेश किया कि उपभोक्ता ने अपना 500 रुपये मासिक वाला प्लान बदलवा कर दूसरा बड़ा प्लान ले लिया था। इतना बड़ा फ़र्जीवाड़ा और वह भी कोर्ट के सामने करने में विभाग को कतई कोई भय नहीं लगा। भय लगे भी क्यों, क्योंकि सब जानते हैं कुछ भी फ़र्जीवाड़ा कर लो, सब चलता है। कोर्ट ने इस फ़र्जीवाड़े व केस की सारी सच्चाई को समझते हुए इस संवाददाता के हक में दिनांक 9 सितम्बर को फ़ैसला दे दिया, परन्तु धोखा-धड़ी, कोर्ट को गुमराह करने, तथ्यों को छिपाने फ़र्जी दस्तावेज़ तैयार करके कोर्ट में पेश करने को लेकर विभाग के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। विभाग के विरुद्ध कार्यवाही के नाम पर कोर्ट ने उन पर केवल 228 रु. बतौर हर्जा-खर्चा डाला, जिसे लेने के लिये एक कवायद अलग से करनी होगी; क्यों न बलिहारी जायें ऐसी अदालतों पर।

गौरतलब है कि चार साल तक तो इस संवाददाता ने यह केस लड़ा। तीन तारीखें सैशन में व दर्जनों तारीखें ट्रायल कोर्ट में लगी। चार बार इस संवाददाता को बयान दर्ज कराने कोर्ट जाना पड़ा। 6 लाइन का बयान लिखने वाले को 200 रुपये बतौर फ़ीस देनी पड़ी। ट्रायल कोर्ट में शिव कुमार जोशी व सैशन कोर्ट में वरिष्ठ वकील ओपी शर्मा को पेश होना पड़ा। शुकर यह रहा कि दोनों वकील संवाददाता के खास दोस्त होने के नाते मुफ़्त में लड़े। वरना वकीलों की फ़ीस व कोर्ट के खर्चे तो टेलिफ़ोन वालों के बिल से कई गुना ज़्यादा हो जाते। शायद विभाग ने भी यही सोचा होगा कि एक बार जैसे-तैसे अपने हक में फ़ैसला ले लें तो कौन केस लड़ता फ़िरेगा।

कुल मिलाकर इस वाहियात एवं फ़र्जी केस का बोझ कोर्ट ने चार साल तो एक बार ढोया और 6 साल जब ढोया जब उन्होंने 2011 में केस दायर किया था। यानी कुल मिलाकर न्यायपालिका ने 10 साल तक उस अवांच्छित मुकदमे का बोझ ढोया जिसे तुरन्त ही, पहली पेशी के बाद, विभाग पर भारी जुर्माने के साथ रद्द किया जा सकता था।

'साहस की पत्रकारिता' भी बिक गई

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

बीते करीब साढे चार साल तक यूपी की जनता को ठगने व बहकाने के बाद अब चुनाव की बेला में अपनी हार को निश्चित पाकर यूपी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने गोयबेल्स के फ़ार्मूले का सहारा लेकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का कुत्सित अभियान चला दिया है। इस अभियान के दौरान अजय सिंह बिष्ट ने दिल्ली से छपने वाले अंग्रेजी अखवार इन्डियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर, बीते सप्ताह अपना एक विज्ञापन छपवाया। अपनी आदम कद मनमोहक तस्वीर के साथ लिखा गया था कि 'यूपी बदल रहा है'। क्या बदल गया, यह दर्शाने के लिये कलकत्ता का एक शानदार फ्लाईओवर तथा अमेरिका की एक फैक्ट्री को दिखाया गया था।

अनपढ़ एवं मूर्ख जनता इस विज्ञापन से शायद यह धोखा खा जाय कि वाकई यूपी, अब वह यूपी नहीं रह गया जहां खड्डों में सड़कें व विकास के नाम पर भूखमरी हो। अब यहां आलीशान सड़कें, फ्लाईओवर व भरपूर रोजगार उपलब्ध कराने के लिये बिष्ट ने राज्य में कारखाने खड़े कर दिये हैं। जनता शायद बहक भी जाती परन्तु आज का सोशल मीडिया भला कहां बहकने देता है; तुरन्त इस झूठ का पर्दाफ़ाश करते हुए समाचार बड़ी संख्या में तैरने लगे। शाम होते तक पूरे देश को पता चल गया कि योगी के वेष में पाखंडी बिष्ट ने अपनी जनता को भ्रमित करने के लिये, करोड़ों रुपये खर्च करके यह जाल फेका था। यह पैसा भी कोई उन्होंने अपने घर से नहीं बल्कि करदाता से वसूले खजाने से ही लगाया था।

जब दुनिया भर में बिष्ट की थू-थू होने लगी तो इन्होंने अपने बचाव में इस तथाकथित 'साहस की पत्रकारिता' करने वाले इन्डियन एक्सप्रेस को अपनी ढाल बना लिया। आये दिन विज्ञापनों के रूप में भारी भरकम रकम देने वाले अपने आकाओं को भला यह अखवार कैसे इन्कार कर सकता था? सो, झट से अखवार की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि उक्त तस्वीरें उनके मार्केटिंग डीविजन की गलती से लगी हैं। मीडिया की थोड़ी-बहुत समझ रखने वाला भी यह बात समझता है कि प्रकाशित होने वाला कोई भी विज्ञापन, मीडिया कम्पनी अपनी ओर से नहीं बनाकर लगाती।

सरकार द्वारा जारी होने वाले विज्ञापनों को तैयार करने के लिये बाकायदा लोकसम्पर्क विभाग होता है। इसमें अनेकों छोटे-मोटे अफ़सरों के अलावा बड़े आईएएस अधिकारी भी होते हैं। प्रत्येक विज्ञापन छोटे अफ़सरों से लेकर उच्चतम अफ़सरों के हस्ताक्षर होने के बाद मीडिया को दिया जाता है। चर्चित विज्ञापन जैसे सम्वेदनशील मामलों में अन्तिम स्वीकृति खुद सीएम द्वारा दी जाती है। इन्डियन एक्सप्रेस एवं खूद सीएम चाहे कितना ही झूठ बोल लें कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं कि चर्चित विज्ञापन अखवार वालों की गलती से छपा है।

खबर मरम्मत

- जुम्मन मियां पंक्चर वाले

छात्रों के चेक बाऊन्स-ठेकेदारों को टनाटन

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा टॉपर छात्रों को दिये चेक बाऊन्स हो गये यानी उनका पैसा तो मिला नहीं उल्टा दो-तीन सौ रुपये बैंकों ने छात्रों से जरूर वसूल लिये-चैक बाऊन्स के चार्जेज के नाम पर। बताया जाता है कि पिछले दिनों हाईस्कूल और इंटर मीडिएट के विभिन्न ज़िलों के टॉपरों को मोदी जी ने कुछ राशि इनाम स्वरूप चेक द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ प्रदान की थी। लेकिन जब बैंक में छात्रों ने ये चेक जमा कराये तो इनामी पैसा तो मिला नहीं उल्टा बैंकों ने छात्रों से अपनी फ़ीस के रूप में दो-तीन सौ रुपये जरूर वसूल लिये।

वैसे तो ठीक किया योगी जी समय रहते इन छात्रों की अक्ल ठिकाने लगा दी वरना ये पढाक थोड़े दिनों बाद सरकार से नौकरी भी मांगते। पर योगी जी ये ठेकेदारों के चेक कभी क्यूं नहीं बाऊंस होते?

पेगासस और नेटग्रिड

सरकार द्वारा इजरायल से खरीदे एक प्रोग्राम पेगासस से अपने नागरिकों की जासूसी करने का मामला कोर्ट में चल ही रहा था कि इसी तरह के एक और कार्यक्रम की खबर आयी है। बताया जाता है कि नेटग्रिड नाम से तैयार यह सॉफ्टवेयर जल्द ही मोदी जी द्वारा लांच यानी उद्घाटन किया जायेगा। इसमें इंटेलीजेंट डेटाबेस है यानी गुप्त रूप से इकट्ठा किये गये नागरिकों के आंकड़े सुरक्षित रहेंगे। उधर पेगसस में सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देने से मना कर दिया कि उसने जासूसी के लिये पेगासस खरीदा या नहीं और उससे नागरिकों की जासूसी करवाई या नहीं और इधर नया जासूसी तंत्र नेहग्रिड तैयार।

यानी न रोजगार देंगे, न शिक्षा देंगे, न अस्पताल, पर तुम पर नज़र पूरी रखेंगे कि कहीं हमारे निकम्मेपन की सज़ा देने की कोई तैयारी तो नहीं कर रहे हो।

योगी का हाथ और कलकत्ता फ्लाइओवर का साथ

रविवार 12 सितम्बर को इंडियन एकस्प्रेस अखबार में छपे एक मुख पृष्ठ विज्ञापन में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा यूपी में किये गये विकास कार्यों का ढोल पीटा गया था। इस विज्ञापन में दिखाये गये विकास कार्यों में कलकत्ता में एक नये बने फ्लाईओवर का भी फ़ोटो है। इस पर विवाद मचा है। हालांकि अखबार ने अपनी ग़लती मानते हुये इस फ्लाइओवर की फ़ोटो अपने डिजीटल संस्करणों से हटा दी है। पर लोग हैं कि मान ही रहे। अब ये भी तो हो सकता है कि फ्लाइओवर योगी जी ने ही बनवाया हो। क्यूंकि डबल ईजन की यूपी सरकार ने इतना ज़यादा विकास कर दिया हो कि यूपी में जगह ही न बची हो इसलिये योगी जी ने कलकत्ता में भी एक फ्लाइओवर बनवा दिया हो। लोग नाहक ही योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उधर तो अब्बा जान बोल रहे हैं और इधर आपा जान का विकास चुरा कर दिखा रहे हैं।

अन्तिम मिसरा

मेडिकल के छात्रों को दीनदयाल और हेडगेवार पढ़ाने की क्या तुक है?

क्योंकि मेडिकल के छात्र ही इन असली बीमारियों के बारे में नहीं पढेंगे तो कौन पढ़ेगा?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06